भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3385

दिनांक 16 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

ओडिशा में पनधारा परियोजनाएं

3385. श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ओडिशा, जो मुख्यतः एक वर्षा-आधारित राज्य है, के लिए नई पनधारा परियोजना को अनुमोदित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या 76 आईडब्ल्यूएमपी पनधारा परियोजना का कार्य सुचारू ढंग से पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार का केन्द्रीय सहायता जारी करने पर पुनर्विचार करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2009-10 से वर्षा सिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को कार्यान्वित कर रहा था। तदनन्तर, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में समामेलित कर दिया गया और सभी चालू परियोजनाओं के पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, अन्य राज्यों की तरह, ओडिशा सरकार को सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित अनुदान दिए गए हैं। चूंकि, सरकार सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए 2015-16 से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत नई परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गई है।

ओडिशा में, वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान, 2191.50 करोड़ रूपए की कुल लागत पर 17 लाख हेक्टर के क्षेत्र को कवर करते हुए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी) के तहत 310 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। अब तक, ओडिशा सरकार को 1089.17 करोड़ रूपये की राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी की जा चुकी है। परियोजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, 310 स्वीकृत परियोजनाओं में से 76 तैयारी चरण की परियोजनाएं राज्य बजट से कार्यान्वित करने के अनुरोध के साथ 01.08.2018 को राज्य को हस्तातंरित की गई थी।

01.03.2021 की स्थिति के अनुसार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्त पोषित की जा रही शेष 234 परियोजनाओं में से 195 परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना मिली है और 39 परियोजनाएं कार्य चरण में हैं। राज्य से प्राप्त सूचना के आधार पर, 01.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 16.71 करोड़ रूपये की अव्ययित शेष राशि उपलब्ध है।

*****